



उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में कृषि उद्यमिता की संभावनाएं : एक मूल्यांकन

सुनील कुमार जायसवाल
अर्थशास्त्र विभाग, किसान पी जी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश
,sunil.jaiswal5894@gmail.com

डॉ विवेक कुमार जायसवाल
(असिस्टेंट प्रोफेसर), अर्थशास्त्र विभाग
किसान पी जी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.16785663>

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-07-2025

Published: 10-08-2025

Keywords:

कृषि उद्यमिता, ग्रामीण विकास,
नवाचार, कृषि अर्थव्यवस्था,
रोजगार

ABSTRACT

भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसमें देश के कुल निर्यात का लगभग 15% हिस्सा कृषि आधारित उद्योगों से प्राप्त होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि उद्यमिता एक आधारभूत स्तंभ के रूप में दिखाई पड़ता है, जो ग्रामीण परिवेश के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन में अग्रणी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। कृषि एवं खाद्य परसंस्करण उद्योग श्रम गहन होने के कारण रोजगार सृजन की संभावना को बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन पहुंचाने में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान प्रमुख है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों जैसे निर्माण, कारोबार, सेवा क्षेत्र, रियल एस्टेट आदि के मुकाबले यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024- 25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) में 7.5 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। कृषि उद्यमिता में तकनीकी नवाचार से कृषक को 'उत्पादक' से उद्यमी बनने का अवसर प्राप्त होता है। यह ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और सभी किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इस दिशा में सरकार उद्योगों को स्थापित करने संबंधी नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके किसानों के अनुकूल बनाने का काम कर रही है। कृषि आधारित

उद्योगों की बुनियादी सेवाओं के विकास से ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों में मजबूती आयी है, इसलिए कृषि उद्यमिता को प्रदेश के विकास के प्रमुख उत्प्रेरक एवं संवाहक के रूप में देखा जा सकता है।

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिसके संचलन में कृषि उद्यमिता मुख्य आधार है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग एक ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान सर्वाधिक है। वर्ष 2024- 25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)में 7.24 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023- 24 के अंत में उत्तर प्रदेश की(जीएसडीपी) 25.48 लाख करोड़ थी जो अगले वित्तीय वर्ष 2024- 25 में बढ़कर 31.94 लाख करोड़ हो जाएगी । लगातार विकास के कारण अगले तीन वर्ष(2027-28) तक राज्य की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है।

पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में प्रभावी बदलाव देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन से यह खेत- खलिहान से आगे बढ़कर कृषि उद्यमिता की तरफ अग्रसर है। ग्रामीण परिवेश में अनेक क्रियाएं जैसे पशुपालन, डेयरी,पोल्ट्री, मछली पालन इत्यादि में कृषि उद्यमिता बढ़ रही है। तकनीकी नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास से कृषि क्षेत्र में अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं जो ग्रामीण रोजगार में वृद्धि के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सकारात्मक सुधार करते हैं।

प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता, विपणन में सुधार, प्रोत्साहन, तकनीकी मार्गदर्शन, यातायात की सुविधा जैसे अनेक कदम मजबूती से उठाने की आवश्यकता है । तकनीकी नवाचार से कृषि की अनेक समस्याओं का समाधान होता है, इस संदर्भ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में **एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज** कार्यक्रम चलाया था जिसमें कृषि से संबंधित 12 समस्याओं के लिए नवाचारी समाधान शामिल किए गए थे, इनमें मिट्टी की जांच से लेकर सूचना,संचार , उपज अनुमान आदि को बढ़ाने के उपाय शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्र में इन सभी प्रयासों एवं उपायों के बावजूद अभी भी बहुत सी समस्याएं एवं चुनौतियां जैसे परिवहन , सड़क, संचार , ऊर्जा , पानी आदि बुनियादी सेवाएं अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं इन सभी चुनौतियां एवं समस्याओं को देखते हुए कृषि उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण विकास में कृषि उद्यमिता की संभावनाओं का अध्ययन करना।
2. कृषि उद्यमिता से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न चरों का अध्ययन करना।



4. ग्रामीण रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
5. कृषि उद्यमिता में तकनीकी नवाचार का अध्ययन करना।

आंकड़ों का संग्रहण

यह शोध पत्र द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है। इसका संकलन समाचार पत्र, जर्नल, पत्र पत्रिका एवं अनेक पुस्तकों की सहायता से किया गया है। आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में कृषि उद्यमिता की संभावनाएं एवं तकनीकी नवाचार

कृषि उद्यमिता का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। कृषि उद्यमिता के लिए कृषि क्षेत्र का विकास होना आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार होने से कृषि उद्यमिता के लिए अनेक अवसर पैदा हुए हैं। कृषि आधारित उद्योगों में मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, मछली पालन, डेयरी, खाद एवं परसंस्करण उद्योग आदि शामिल हैं, जो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इस दिशा में सरकारी प्रयास भी किया जा रहे हैं। भारत सरकार समय-समय पर कृषि संबंधित नीतियां एवं कार्यक्रम लागू करती रहती है इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता, जोखिम घटना, अवसंरचना का निर्माण करना, किसानों को मजबूती प्रदान करना, कृषि उद्यमिता में नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल है।

उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थिति तालिका न.1

क्रमांक	उद्योग का नाम /उत्पाद	मुख्य क्षेत्र (जिले)	संभावित रोजगार	वार्षिक उत्पादन मूल्य (रु करोड़ में)
1	चीनी उद्योग (चीनी, एथेनॉल)	मेरठ, बरेली, गोंडा	1.2लाख	रु 30,000
2	खाद्य प्रसंस्करण (पापड़ आचार)	कानपुर लखनऊ वाराणसी	90,000	रु 7000
3	डेयरी उद्योग(दूध घी पनीर)	आगरा अलीगढ़ अम्बेडकर नगर	80,000	रु 12000
4	कपास /जूट उद्योग (कपड़ा, सूत)	झांसी बादा प्रयागराज	20,000	रु 1200
5	मुर्गी पालन /पोल्ट्री (अंडा, चिकन)	कानपुर फतेहपुर	50,000	रु 3000
6	मछली पालन उद्योग	संतकबीर नगर बस्ती बलरामपुर	25,000	रु 1000

श्रोत - सांख्यिकी निदेशालय उत्तर प्रदेश (statistical dairy-2023)



मधुमक्खी पालन

कृषि आधारित उद्योगों में मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण स्टार्टअप है। इसे मीठी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रशिक्षण और 40% सब्सिडी प्रदान करती है। इससे शहद, मोम, पराग, जेली जैसी महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्रदेश में बहुत से किसान मधुमक्खी पालन को अपना रहे हैं, इससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में लगभग 22 से 23 हजार टन शहद का उत्पादन होता है। लखनऊ, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, अयोध्या जैसे जिलों में मधुमक्खी पालन करके शहद का उत्पादन किया जा रहा है। ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए मधुमक्खी पालन सुनहरा अवसर है।

उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी पालन की स्थिति तालिका न 2

विवरण	आंकड़े (2023-24)
मधुमक्खी का कारोबार करने वालों की संख्या	लगभग 25000
प्रमुख क्षेत्र	मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, सहारनपुर, बागपत
कुल शहद का उत्पादन	12000 मिट्रिक टन प्रति वर्ष
औसत उत्पादन प्रति बॉक्स	25-30किग्रा प्रति सीजन
मधुमक्खी की प्रजातियाँ	Apis mellifera, Apis cerana indica
निर्यात किए गए शहद का मूल्य	रु 100 करोड़ से अधिक
प्रशिक्षण केंद्र	IIVR वाराणसी, कृषि विज्ञान केंद्र
सरकारी योजना	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व मधु मिशन (NBHM)

श्रोत - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

डेयरी उद्योग लगाना

देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का 16% योगदान है। वर्ष 2024 में प्रदेश में डेयरी बाजार का आकार 2083.7 बिलियन रुपए था, जो वर्ष 2033 तक 5911.7 बिलियन रुपए तक पहुंचाने की उम्मीद है। दूध से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे घी, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि का निर्माण किया जाता है, जिसमें छोटे स्तर के डेयरी उद्योगों के द्वारा हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। दिन प्रतिदिन दूध का उत्पादन राज्य में बढ़ता जा रहा है। दूध से बने उत्पादों को बाजार में बेचे जाने से ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन - तालिका न 3

वर्ष	दूध का कुल उत्पादन (लाख टन)	देश के कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी(%)	प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता (ग्राम/प्रतिदिन)
2018-19	290.56	16.9%	359
2019-20	298.24	17.2%	370
2020-21	307.22	17.3%	378
2021-22	315.35	17.4%	386
2022-23	323.45	17.5%	395

श्रोत - उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में दूध का उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। दूध से बने उत्पादों को बाजार में बेचे जाने से ग्रामीण लोगों की आय स्तर में वृद्धि तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है।

चीनी उद्योग

कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है पेराई सत्र (2023 -24)में राज्य में कुल 121 चीनी मीले संचालित थी। प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 29.66 लाख हैक्टेयर भूमि पर होता है, जिसकी उत्पादकता 841 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यह राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 3 प्रतिशत का योगदान देता है। चीनी उद्योग प्रदेश के 50 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है, यह कृषकों की आय को बढ़ाने में मदद करता है साथ ही साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है

उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की स्थिति - तालिका न 4

वर्ष	एरिया (लाख हैक्टेयर)	औसत उत्पादन (टन/प्रति हेक्टेयर)
2020-21	22.7	80.1
2021-22	23.08	81.5
2022-23	23.45	82.6
2023-24	23.90	83.2

श्रोत - UP cane development department report 2022-23

उत्तर प्रदेश में प्रमुख चीनी मिलों की स्थिति तालिका न 5

प्रमुख मीले	जिला
अकबरपुर चीनी मिल्स लिमिटेड	अंबेडकर नगर
बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड	बलरामपुर,गोंडा
बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड	लखीमपुर खीरी
कुपरगांव शुगर मिल्स	सहारनपुर

श्रोत - Company annual report (e.g.balrampur chini mills)

धान की भूसी से कलातियां

प्रदेश के अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान है, जिसमें अनेक फसलों का उत्पादन होता है। धान का उत्पादन राज्य में मुख्य रूप से किया जाता है। धान की भूसी एक 'वेस्ट' होता है जो पर्यावरण अनुकूल नहीं होता है, इसे पर्यावरण अनुकूल बनाना किसानों के लिए एक चुनौती है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में धान की भूसी से किसानों द्वारा कलाकृतियां बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों ने धान की भूसी से सुन्दर आकार वाली हैगिंग, सजावट के समान इत्यादि बनाकर सफलतापूर्वक अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में धान की भूसी की उपलब्धता अधिक होती है जिससे ग्रामीण युवा इस कला को सीख कर अपनी आय को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं जो ग्रामीण जनजीवन को रूपांतरित करने में मदद करेगा।

मशरूम की खेती

कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने में मशरूम की खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसान नई-नई तकनीक के माध्यम से मशरूम की खेती कर रहे हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे महानगरों में इसकी मांग बढ़ रही है। मशरूम की खेती करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पूंजी में ही इसकी खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसकी खेती करने के लिए तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है। मशरूम की खेती निश्चित रूप से ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगारों के लिए सुनहरा अवसर है इसके तकनीकी ज्ञान के लिए कृषि विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय मशरूम केंद्र से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में मशरूम की खेती तालिका न 6

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1	मशरूम का कुल उत्पादन (2023-24)	3500 मिट्टिक टन लगभग
2	उत्पादक क्षेत्र	लखनऊ, वाराणसी ,मेरठ, गोरखपुर ,सीतापुर
3	क्षेत्रफल	1200 हेक्टेयर लगभग
4	लाभ पाने वाले किसानों की संख्या	लगभग 12000
5	औसत उत्पादन प्रति यूनिट	10 - 12 किग्रा/ दिन / शेड
6	सब्सिडी	40-60%
7	मशरूम के प्रकार	बटन मशरूम, मिल्की, शिटाके

चुनौतियां एवं समाधान

राज्य में पिछले कुछ वर्षों में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा मिला है, जिसने ग्रामीण अवसंरचना को सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया है। किंतु कृषि उद्यमिता को तीव्र गति से बढ़ाना अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण ग्रामीण किसानों के लिए कृषि उद्यमिता को अपना आसान नहीं है, गरीब किसान कम शिक्षित होने के कारण शून्य जोखिम पर काम करना चाहता है। कृषि उद्यमिता के लिए एक अन्य समस्या घटती जोत और कम उपज है, जो किसानों को कृषि आधारित उद्योगों के अलावा अन्य व्यवसाय करने के लिए बाध्य कर देती है। यह कृषि उद्योगों के लिए एक नुकसान देहत स्थित है। कृषि उद्यमिता की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए, अनेक शैक्षिक संस्थानों में कृषि उद्यमिता को पाठ्यक्रम के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, कृषि के अन्य तत्व मिट्टी, पानी, बीज, सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। कृषि उद्यमिता को सफल बनाने के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का सही तालमेल होना चाहिए। इस तरह का प्रयास कृषि उद्यमियों को स्वावलंबी बनने में मदद करेगा।



निष्कर्ष

कृषि उद्यमिता अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जहां पर अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। जिसे दूर करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 में राज्य में 121 चीनी मीले कार्यरत थी, जो प्रदेश के लगभग 50 लाख से अधिक किसानों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2024 में राज्य में डेयरी बाजार का आकार 2083.7 बिलियन था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना राज्य के समावेशी विकास के लिए मूलभूत अवसर और परिवेश को पैदा करने का काम करेगा। इससे एक तरफ मानव पूंजी में वृद्धि तथा दूसरी ओर आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि आएगी। कृषि उद्यमिता पर्यावरण प्रबंधन में सहायता करेगा साथ ही साथ दूरगामी विकास के लिए दिशा निर्धारित करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- कुमारी गीता(2010) : कृषि उद्यमिता का अध्ययन मेरठ जनपद के संदर्भ में (शोध प्रबंध)
- के पी सुंदरम एवं रुद्र दत्त भारतीय अर्थव्यवस्था 2014: एस चन्द्र एंड कंपनी लिमिटेड राम नगर नई दिल्ली
- राकेश आर्या (1999): कृषि आधारित उद्योग एवं ग्रामीण विकास पर शोध प्रबंध मालवा पठार के संदर्भ में
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि सांख्यिकी एक नजर में, 2020
- मोदी अनीता (2012): ग्रामीण भारत बदलती तस्वीर वाइकिंग बुक्स जयपुर
- कुमुद सिंह (2008): उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में कृषि उद्यमिता की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (शोध प्रबंध)
- वार्षिक रिपोर्ट (2023-24): कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग नई दिल्ली
- कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका 2022
- कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका 2024
- आर्थिक समीक्षा 2023-24
- Annual survey industry report 2013-14
- उत्तर प्रदेश सरकार - कृषि विभाग (<http://upagriparadarshi.gov.in>)
- MSME विभाग उत्तर प्रदेश (<https://msme.gov.in>)
- राष्ट्रीय खाद्य परसंस्करण मिशन (<https://mofpi.nic.in>)
- Statistical diary of U P -2023
- <https://icar.org.in>



- <https://www.vivacepanorama.com/agro-based-industry/>
- <https://www.ruralvoice.in/national/Uttar-pardesh-lags-again-maharatshttra-in-sugar->